

प्रेस विज्ञप्ति

**जामिया के सरोजिनी नायडू महिला अध्ययन केंद्र ने LSE प्रोफ़ेसर नाइला कबीर का
'रिनेगोशिअटिंग पेट्रिआर्की: जेंडर, एजेंसी एंड द बंगलादेश पैराडॉक्स' विषय पर ऑनलाइन
लेक्चर आयोजित किया**

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2026

'विशिष्ट व्याख्यान श्रृंखला' के एक हिस्से के तौर पर, सरोजिनी नायडू महिला अध्ययन केंद्र ने लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग में 'जेंडर एंड डेवलपमेंट' की प्रोफ़ेसर एमेरिटस, प्रोफ़ेसर नाइला कबीर को 'रिनेगोशिअटिंग पेट्रिआर्की: जेंडर, एजेंसी एंड द बंगलादेश पैराडॉक्स' विषय पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। इस सत्र में इस बात पर चर्चा की गई कि आर्थिक चुनौतियों के बावजूद बांग्लादेश ने किस तरह उल्लेखनीय सामाजिक प्रगति हासिल की; इसमें पितृसत्तात्मक ढांचों को पूरी तरह से खत्म करने के बजाय, उन्हें नया रूप देने में महिलाओं की 'एजेंसी' (सक्रिय भूमिका) पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रोफ़ेसर कबीर ने समझाया कि बांग्लादेश की प्रगति 'गरीब-समर्थक' होने के साथ-साथ 'लैंगिक रूप से भी न्यायसंगत' रही है। इस प्रगति को शिक्षा नीतियों, परिवार नियोजन पहलों, NGO के हस्तक्षेपों और गारमेंट इंडस्ट्री में उपलब्ध अवसरों से बल मिला है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि महिलाओं की 'एजेंसी' किस तरह विविध रूपों में सामने आई—छिपे हुए विरोध से लेकर खुलकर मोल-भाव करने तक—और कैसे इन व्यक्तिगत कार्यों ने सामूहिक रूप से मिलकर एक परिवर्तनकारी सामाजिक बदलाव को जन्म दिया।

केंद्र की पीएचडी शोधार्थी प्रीति मौर्य ने सत्र की शुरुआत की। इसके बाद, सरोजिनी नायडू महिला अध्ययन केंद्र की मानद निदेशक प्रोफ़ेसर निशत ज़ैदी ने स्वागत वक्तव्य दिया और वक्ता का परिचय कराया। प्रोफ़ेसर कबीर ने बांग्लादेश के विकास के उस अनूठे मॉडल पर चर्चा की, जो यूरोपीय-अमेरिकी विकास प्रतिमानों से अलग है। उन्होंने परिधान उद्योग में श्रम-शोषण जैसी चुनौतियों के बावजूद, महिलाओं की 'एजेंसी' और उनके आर्थिक सशक्तिकरण पर ज़ोर दिया। उन्होंने बांग्लादेश की महिला प्रधानमंत्रियों के प्रभाव से जुड़े सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि यद्यपि इन महिला प्रधानमंत्रियों ने महत्वपूर्ण 'रोल मॉडल' की भूमिका निभाई और कई लाभकारी नीतियां लागू कीं, लेकिन अंततः उन्हें भी सत्ता की राजनीति से जुड़ी वैसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने 1971 के युद्ध और 'बिरांगनाओं' के अनुभवों पर भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने समझाया कि जब युद्ध के दौरान पुरुष महिलाओं की रक्षा करने में विफल रहे, तब महिलाओं को यह एहसास हुआ कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था के तहत होने वाला 'समझौता' अब और मान्य नहीं रह गया है। पितृसत्तात्मक ढांचों पर पुनर्विचार करने की जटिलताओं को रेखांकित करते हुए, उन्होंने परिधान उद्योग में काम करने वाली महिलाओं के सामने आने वाली "दोहरी दुविधा" के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि कृषि या घरेलू काम की तुलना में इस क्षेत्र में बेहतर अवसर तो उपलब्ध थे, लेकिन वे अवसर भी अंततः शोषणकारी ही बने रहे। इसके अलावा, उन्होंने घरेलू हिंसा, GDP में अनपेड केयर वर्क को मान्यता देने, और महिलाओं की भूमिकाओं तथा उनके नेतृत्व के प्रति लोगों के दृष्टिकोण पर धार्मिक शिक्षा के प्रभाव जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की। प्रोफ़ेसर कबीर ने सशक्तिकरण का अपना त्रि-आयामी मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें एजेंसी, संसाधन और उपलब्धियां शामिल हैं। उन्होंने समझाया कि शिक्षा किस प्रकार

आत्मविश्वास बढ़ाकर और स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनाकर व्यक्तियों में बदलाव ला सकती है। चर्चा में कट्टरपंथी संगठनों द्वारा पेश की जाने वाली चुनौतियों पर भी बात हुई; प्रोफेसर कबीर ने इस बात का ज़िक्र किया कि ये संगठन राजनीतिक लाभ के लिए खुद को अधिक उदार दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बांग्लादेश के 'ग्रामीण बैंक' के ऋण-आधारित मॉडल की तुलना भारत के 'स्वयं-सहायता समूह' मॉडल से की, और बताया कि ग्रामीण बैंक ने सामाजिक शिक्षा के बजाय गरीबी उन्मूलन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया।

व्याख्यान के बाद एक बेहद दिलचस्प प्रश्नोत्तर सत्र हुआ, जिसमें स्कॉलर्स और शिक्षकों ने मिलकर चर्चा को और आगे बढ़ाया। इस व्याख्यान में पूरे भारत से आए शिक्षकों और विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया, जो प्रोफेसर कबीर की लोकप्रियता और इस व्याख्यान श्रृंखला के महत्व को दर्शाता है। प्रोफेसर कबीर ने अपने समापन भाषण में कहा कि जहाँ एक ओर बांग्लादेश लगातार आर्थिक विकास कर रहा है, वहीं दूसरी ओर असमानता और शासन-प्रशासन से जुड़ी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। उन्होंने नए BNP नेतृत्व के अंतर्गत अधिक समावेशी नीतियां बनने की संभावनाओं को लेकर आशा व्यक्त की।

व्याख्यान का समापन डॉ. अमीना हुसैन द्वारा दिए गए धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ; डॉ. हुसैन 'विशिष्ट व्याख्यान श्रृंखला' की समन्वयक हैं और उन्होंने 'सरोजिनी नायडू महिला अध्ययन केंद्र' की ओर से यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह 'विशिष्ट व्याख्यान श्रृंखला' स्कॉलर्स के आपसी विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करती आ रही है, जो विभिन्न विषयों के बीच संवाद को बढ़ावा देती है और नारीवादी शोध के क्षेत्र में गहन व आलोचनात्मक दृष्टिकोणों को आगे बढ़ाती है।

प्रो. साइमा सईद
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी